

महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा के चुनाव नतीजों का असर नहीं होगा

क्योंकि हरियाणा में भाजपा का मुकाबला सीधे कांग्रेस से था, पर, महाराष्ट्र में कांग्रेस, गठबंधन की जूनियर पार्टनर मात्र है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर दो सौ अठ्यासी सौ दो बाले महाराष्ट्र तथा 81 सीटों वाले आदिवासी बहुल झारखंड के विधानसभा चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब हरियाणा के चौका देने वाले परिणामों ने इन दोनों राज्यों के चुनावों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र में विरोधाभास साफ जाहिर हैं। एक तरफ तो भाजपा, एकनाथ शिंदे सरकार, जो भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग तथा लोक-लुभावण योजनाओं के नाम पर राजकोष को खाली कर देने के आरोपों से जूझ रही है, को समर्थन दे रही है। वहीं बिड़म्बना यह है कि झारखंड में भाजपा सत्ता में आने के लिये जे.एम.एम. सरकार पर यही आरोप लगा रही है।

हरियाणा में, भाजपा ने कॉर्ट की टक्कर के तहत बिखरी हुई कांग्रेस को मात दे दी थी। उसका आंशिक कारण तो यह रहा कि कांग्रेस, भाजपा से कुल 22,000 वोटों के अन्तर से 9 सीटें हार गईं, जिसमें इंडियन नेशनल लोक दल (आई.एन.एल.डी.) से हारी सीट भी

■ महाराष्ट्र में भाजपा के पास शरद पवार व उद्धव ठाकरे जैसा करिश्माई नेता भी नहीं है। हालांकि भाजपा ने शरद पवार को कमजोर करने के लिए अजित पवार का और उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे का प्रयोग किया, पर, उसे सफलता नहीं मिली।

■ जबकि, हरियाणा में भाजपा का सामना धरातल पर बिखरी हुई व गुटबाजी से त्रस्त कांग्रेस से था, यही वजह रही कि कांटे की टक्कर में भाजपा ने जीत हासिल कर ली।

शामिल हैं। लेकिन महाराष्ट्र एवं झारखंड की चुनावी स्थितियाँ पूरी तरह भिन्न हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस, गठबंधन में जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तथा शरद पवार एवं झारखंड में हेमन्त सोरेन की टक्कर के करिश्माई नेता भाजपा के पास नहीं है, इसीलिये भाजपा पूरी तरह से नरेन्द्र मोदी की छवि और अमित शाह की राजनैतिक चतुराई पर भरोसा करने के लिए मजबूर है।

महायुति गठबंधन में अजित पवार सबसे कमजोर कड़ी माने जाते हैं। अभी हाल ही तक, वे अपने चाचा शरद पवार

के गुट में लौटने के लिये, उनसे समझौता वार्ता करने की कोशिश कर रहे थे। जब वे एन.सी.पी. को तोड़कर, भाजपा के पक्ष में गये थे, उस समय इ.डी. 80,000 करोड़ रूपए के सिंचाई घोटाले में उनके खिलाफ जांच करने वाला था। लेकिन उनकी सारी परेशानियाँ भाजपा में शामिल होने के बाद समाप्त हो गईं। दरअसल, अजित पवार का प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्रों में ही है, जबकि शरद पवार का जनाधार व्यापक और मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनावों में, अजित पवार जैसे-तैसे एक सीट जीत पाये थे तथा

उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले से बरामती सीट पर बुरी तरह हार गई थीं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिव सेना लोकसभा चुनाव में 7 सीटें तथा भाजपा मात्र 9 सीटें जीत पाई थी। शिंदे गुट, लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर, अब सीटों के आनुपातिक आवंटन पर जोर दे रहा है। लेकिन चुनावों की घोषणा होते ही, भाजपा ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिये हैं तथा शिंदे और पवार गुट को दरकिनार कर दिया है। बताया जाता है कि भाजपा ने दिल्ली में शिंदे को यह स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा ज्यादा सीटें प्राप्त करने के उद्देश्य से भाजपा के पक्ष में गये थे, उस समय इ.डी. 80,000 करोड़ रूपए के सिंचाई घोटाले में उनके खिलाफ जांच करने वाला था। लेकिन उनकी सारी परेशानियाँ भाजपा में शामिल होने के बाद समाप्त हो गईं। दरअसल, अजित पवार का प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्रों में ही है, जबकि शरद पवार का जनाधार व्यापक और मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनावों में, अजित पवार जैसे-तैसे एक सीट जीत पाये थे तथा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या सिद्दीकी की हत्या के लिए हथियार पाकिस्तान से आए थे?

मुम्बई पुलिस को शक है कि हथियार ड्रोन के जरिए भेजे गए थे

मुम्बई, 25 अक्टूबर महाराष्ट्र के राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के दौरान हथियारों के पास पांच अलग-अलग तरह की पिस्तौलें थीं। मुंबई क्राइम ब्रांच को मामले में गिरफ्तार आरोपी राम कर्नौजिया के घर से एक पिस्तौल मिली। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मुंबई पुलिस ने संदेह जताया है कि ये पिस्तौलें पाकिस्तान से आई हैं। पुलिस को शक है कि ये ड्रोन के जरिए भेजी गईं हैं। इन हथियारों की तस्वीरें राजस्थान पुलिस को भी भेजी गईं हैं।

पुलिस के मुताबिक, पिस्टल रायगढ़ जिले के प्लसपे नाम की जगह से बरामद की गई है, जहां पर आरोपी राम कर्नौजिया का किराए का घर है। पुलिस को इस मामले में अब कुल 4 पिस्टल मिल चुकी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान पता चला कि हथियारों

विख्यात वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले का निधन

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसरों की वकालत करने वाली प्रमुख आवाजों में से एक भौतिक विज्ञानी रोहिणी गोडबोले का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 72 वर्ष की थीं।
पद्म श्री से सम्मानित गोडबोले 25 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में उच्च ऊर्जा भौतिकी केन्द्र से जुड़ी रहीं। उन्होंने 2018

■ प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया।

में सेवानिवृत्ति के बाद मानद प्रोफेसर के रूप में काम किया है। पुणे में जन्मी गोडबोले एसपी कॉलेज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), बॉम्बे की पूर्व छात्रा थीं। बारह नवंबर 1952 को जन्मी गोडबोले ने 1979 में अमेरिका के स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया।
प्रधानमंत्री ने गोडबोले के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने शोक संदेश में कहा, रोहिणी गोडबोले जी के निधन से बहुत दुःख हुआ। वह एक अग्रणी वैज्ञानिक और नवोन्मेषक थीं, जो विज्ञान को दुनिया में अधिक महिलाओं की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केन्द्र सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए नेशनल कानून बनाने और लागू करने का आग्रह किया है। हालांकि इसकी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने इस पर असंतोष जताया है। ज्ञातव्य है कि प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.) एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन संसद ने किया है।
पत्रकारों की गिरफ्तारी, गैर कानूनी तरीके से बन्दी बनाने और धमकाने के

खिलाफ यह प्रस्ताव पी.सी.आई. सदस्य गुरबीर सिंह ने बनाया था, जिसे 27 सितंबर को बहुमत से स्वीकार किया गया था।
इसमें प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया एक्ट को ज्यादा शक्तियाँ देने की मांग की गई है, ताकि यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के लिए उपर रही चुनौतियों व खतरों से निपटने में सक्षम हो सके। सिंह लिखते हैं कि अभी पी.सी.आई. सिर्फ सलाहकारी आदेश ही दे सकती है, जो बाध्यकारी नहीं होता है, इसलिए उन तत्वों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में मांग की गई है कि पुलिस के लोगों को लोकतंत्र

■ प्रेस काउन्सिल की मीटिंग में पत्रकार गुरबीर सिंह ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकारों काउन्सिल के आदेश को उपदेश मात्र मानकर उपेक्षित कर देती हैं तथा आदेश की परवाह नहीं करती हैं और पत्रकारों को धमकाती हैं।
■ प्रस्ताव में बताया गया है कि वर्ष 2023 में भारत में 5 पत्रकारों की हत्या हुई तथा 226 पत्रकारों को सरकारों, राजनेताओं ने और असांजित तत्वों ने निशाना बनाया।
गिरफ्तारी से पूर्व संपादक या प्रकाशन से पुष्टि की जाए कि क्या संबंधित पत्रकार किसी विषय पर काम कर रहा था।
उदाहरण के लिए, एक पत्रकार की

एडिशनल एस.पी. ने 34 लाख में राजीनामा कराया- डी.जी. जाँच करें

जयपुर, 25 अक्टूबर राजस्थान हाईकोर्ट ने सर्वाई माधोपुर के गंगापुर थाने में दर्ज मामले में बिना जांच अधिकारी होते हुए, तत्कालीन स्थानीय एडिशनल एस.पी. की ओर से 34 लाख रूपए में पक्षकारों के बीच राजीनामा कराने के मामले में डी.जी.पी. को जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से वर्दी में नोटों के साथ बैठकर पक्षकारों में राजीनामा कराने को गंभीर माना है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी

■ हाई कोर्ट ने कहा, एडिशनल एस.पी. जाँच अधिकारी नहीं थे, पर वर्दी में नोटों के साथ पक्षकारों के साथ बैठकर समझौता कराया, यह गंभीर मामला है।

का मध्यस्थता कराना व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं माना जा सकता। ऐसे में डी.जी.पी. से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मामले की पुनः जांच कराएँ अन्यथा पूर्व में तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर उसे एडिशनल एस.पी. की सेवा पुस्तिका में लगाया जाए इसके साथ ही, अदालत ने मामले के आरोपी पवन कुमार को जमानत पर रिहा करने को कहा है। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्व अधिकारी-अधिशायी अधिकारी परीक्षा निरस्त

आर.पी.एस.सी. ने हाईटैक डिवाइस से नकल की पुष्टी होने पर यह निर्णय लिया

अजमेर, 25 अक्टूबर (कास)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के आयोजन के दौरान गोपनीयता भंग होने की जानकारी के बाद, राजस्व अधिकारी ग्रेड- द्वितीय एवं अधिशायी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 (14 मई 2023) को निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा के बारे में प्राप्त शिकायतों के संबंध में आयोग ने 12 जून 2024 को शिकायतों की जांच के लिए ए.टी.एस. एवं एस.ओ. जी. को लिखा था। आयोग अब समस्त आवेदित अभ्यर्थियों के लिए 23 मार्च 2025 को पुनः परीक्षा का आयोजन करेगा।

आयोग सचिव के अनुसार, आयोग ने पाया कि परीक्षा आयोजन के दौरान ही कतिपय परीक्षा केन्द्रों पर वांछित शुचिता का पूर्ण अभाव रहा है। कई अभ्यर्थियों द्वारा ब्युत्थ से नकल करने के संबंध में दर्ज तीन प्राथमिक रिपोर्टों, उनके अनुसंधान उपरान्त, अपराध प्रमाणित पाये जाने पर स्पष्ट हुआ है कि राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशायी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) परीक्षा, 2022 (परीक्षा 14 मई

■ अतिरिक्त महानिदेशक एस.ओ.जी. ने 28 अगस्त की रिपोर्ट में आयोग को बताया कि परीक्षा की गोपनीयता के संबंध में गंभीर तथ्य सामने आये हैं।
■ समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा 23 मार्च 2021 को होगी।

2023) को गोपनीयता खंडित हुई है। इसीलिए आयोग ने राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशायी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2022 को निरस्त कर समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा आयोजित किये जाने का निर्णय लिया है।
आयोग द्वारा 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशायी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा-2022 में 1,96,483 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी सूची में कुल 311 अभ्यर्थी सम्मिलित थे।
दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित अभ्यर्थियों के सदिध प्रतीत होने पर आयोग ने भी 02 अगस्त 2024 से

दिनांक 08 अगस्त 2024 तक अनेक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जांच कर पुष्टताख नोट तैयार किया और 14 अगस्त 2024 को अतिरिक्त महानिदेशक, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी. को अंतिम अनुसंधान करने के लिए लिखा था। इस क्रम में ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी., राजस्थान, जयपुर ने 28 अगस्त 2024 को आयोग को अवगत कराया है कि उक्त परीक्षा आयोजन तिथि के दौरान परीक्षा की गोपनीयता के सम्बन्ध में गंभीर तथ्य सामने आये हैं। नकल के इसी प्रकार में 24 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त एस.ओ.जी., जयपुर ने भी एस.ओ.जी. थाना जयपुर में 19 अक्टूबर 2024 को एफ.आई.आर. संख्या 66/2024 दर्ज की गई है एवं अनेक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है।

‘घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध’

नोबल पुरस्कार विजेता कोरिअन लेखक की किताब कोरिया में ही प्रतिबंधित

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। “कोरिअन हैरल्ड” की चाई जॉंग हून ने सिओल से खबर दी है कि दक्षिण कोरिया की उपन्यासकार हन कांग को 2024 का साहित्य का नोबल पुरस्कार मिलने के बाद देश भर में उल्लास का माहौल है, किन्तु, इस सबके बीच कांग की एक किताब को लेकर भारी वाद विवाद छिड़ गया है, जिसे “युवाओं के लिए हानिकारक” माना जा रहा है।
विवाद उस समय शुरू हुआ, जब यह पता चला कि, गत वर्ष ग्वांगी प्रांत के तकरीबन 2490 एलिमेंट्री, मिडिल व हाई स्कूलों की लाइब्रेरी से जो 2528 किताबें हटाई गई थीं, उनमें कांग की किताब “द वैजिटेरियन” भी शामिल थी। हटाई गई सभी पुस्तकों को छात्रों के लिए हानिकारक माना गया था।
इन पुस्तकों में हन कांग की किताब ही नहीं बल्कि, एक और नोबल पुरस्कार विजेता लोक होजे सारागामो की पुस्तक “ब्लाड-डनेस” माइकल रोज़न की, “यू: द ओनर्स मैनुअल”, जिसे जर्मनी

■ किताब में बच्चों को आरम्भ से ही सैक्स एजुकेशन देने की बात कही गई है, जो सारे विश्व में सराही जा रही है, पर, कोरिया के परम्परावादी खेमें ने इस किताब का सख्त विरोध किया है और इस किताब को उन स्कूलों व पुस्तकालयों में प्रतिबंधित कर दिया है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं।

में “साइंस बुक ऑफ द ईयर” अवॉर्ड मिला था तथा टाइम्स एजुकेशनल सॉल्यूशंस सीनियर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड जीतने वाली, सूज़न मैरिडिथ की “वॉट्स हैपनिंग टु मी” शामिल है। आखिरी दो किताबें, किशोरों के लिए सैक्स एजुकेशन तथा मानव शरीर के बारे में हैं।

यह कदम तब उठाया गया, जब ग्वांगी प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ एजुकेशन एक रूढ़िवादी एन.जी.ओ. की सलाह पर स्कूलों को पुस्तकों के बारे में मैमो भेजा। एन.जी.ओ. ने स्कूलों को सैक्स संबंधी किताबें हटाने की सलाह दी थी। तथापि, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एण्ड टूरिज्म के तहत आने वाली पब्लिकेशन इण्डस्ट्री प्रमोशन एजेंसी

ऑफ कोरिया ने हटाई गई किताबों में से केवल एक किताब को युवाओं के लिए हानिकारक माना।
हान की, लिटरेचर में नोबल की ऐतिहासिक जीत के बारे में स्कूलों और घरों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई।
दो बेटियों की माँ, ली ने कहा, “मेरी बेटों, जो आठवीं कक्षा में हैं, ने कहा कि वो हान की किताब “द वैजिटेरियन” पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके टीचर्स ने उसे “ह्यूमन एक्ट्स” नाम की दूसरी किताब पढ़ने की सलाह दी। ली ने आगे कहा, “द वैजिटेरियन” को मेरी बेटों की उम्र के बच्चों के लिए अनुपयुक्त बताया गया।
माताओं के एक लाइन कैफे में एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुशांत डैथ केस में रिया चक्रवर्ती को राहत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सप्ताह के शुरु में सी.बी.आई. तथा महाराष्ट्र की उस अपील को “सारहीन” बताते हुये खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती तथा भाई शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ जारी किये गये “लुक आउट सर्कुलर्स” (एल.ओ.सी.) को रद्द कर दिया गया था।

रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती तथा उनके पिता लेफ्टिनेन्ट कर्नल इन्द्रजीत चक्रवर्ती को “लुक आउट सर्कुलर” सी.बी.आई. द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच के सिलसिले में जारी किये गये थे।

■ सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. द्वारा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक और पिता रिटायर्ड सैन्य अधिकारी इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ जारी “लुक आउट सर्कुलर” को रद्द कर दिया।

एल.ओ.सी. को रद्द कर देने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सी.बी.आई. की याचिका को “सारहीन” बताते हुये, न्यायमूर्ति वी.आर. गवई तथा के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जाँच एजेंसी इस शीर्ष अदालत में केवल इसलिये आई है, क्योंकि आरोपी हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं।

इसके बाद, बेंच ने सी.बी.आई. की याचिका खारिज कर दी। सी.बी.आई. ने इनके खिलाफ एल.ओ.सी. उस समय जारी किये थे, जब राजपूत के परिवार ने पटना में एक एफ.आई.आर. दर्ज करके, राजपूत की मृत्यु की जाँच की माँग की थी।
उच्च न्यायालय ने ये एल.ओ.सी. फरवरी 2024 में रद्द कर दिये थे तथा कहा था कि सी.बी.आई., एल.ओ.सी. जारी करने के कारण नहीं बता पाई है।